

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:— मेघना चौधरी, आर०ए०एस०)

अपील संख्या:—266/2018/223 (2018/00266)

1. श्रीमती गोविन्द कंवर पत्नि स्व० कानसिंह,
  2. जसवंत सिंह पुत्र स्व० कानसिंह,
  3. भवानी सिंह पुत्र स्व० कानसिंह,
  4. अर्जुन सिंह पुत्र स्व० कानसिंह,
- समस्त जाति राजपूत, निवासी बुधवाड़ा, तह० पीसांगन, जिला अजमेर ।  
अपीलांटस

बनाम

1. बुद्धाराम पुत्र चौथाराम, जाति जाट, निवासी बुधवाड़ा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।
  2. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भांवता, जिला अजमेर जरिये मैनेजर ।
  3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।
- रेस्पोंडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय व डिक्ली विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 22.5.2017 अंतर्गत वाद संख्या 30/2016.



उपस्थित:—

1. श्री पुष्पेन्द्र सिंह नरूका, वकील अपीलांटस ।
2. श्री भीयाराम चौधरी, वकील रेस्पोंडेंट संख्या 1.
3. रेस्पोंडेंट संख्या 2 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 3.

निर्णय

दिनांक:— 21.12.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय व डिक्ली दिनांक 22.5.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने अधीनन्यायालय में वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राज०काश्त०अधि० 1955 के तहत विरुद्ध अपीलांटस/प्रतिवादीगण के पेश कर कथन किया कि ग्राम बुधवाड़ा, तहसील पीसांगन में स्थित खाता संख्या नया 179 पुराना 82 में खसरा नंबर 1661 रकबा 0.20 है०, खसरा नंबर 1662 रकबा 0.13 है०, 1666 रकबा 0.13 है०, 1667 रकबा 0.24 है० कुल कित्ता 4 कुल रकबा 0.70 है० भूमि में वादी/रेस्पोंडेंट का 1/2 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी/अपीलांट का 1/2 हिस्सा है जिस पर संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य है । प्रतिवादी/अपीलांट संयुक्त खातेदारी भूमि का बिना विभाजन कराये विशेष भाग पर निर्माण करने एवं विशेष भूभाग को विक्रय करने पर आमादा है । अतः वाद स्वीकार कर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस न्यायिक बंटवारा किया जाकर वादी को खसरा नंबर 1661 व 1662 के कब्जे काश्त अनुसार न्यायिक विभाजन

राजस्थान न्यायालय  
अजमेर

किया जावे । अधी०न्याया० ने दिनांक 22.5.2017 को निर्णय पारित कर वाद में विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की । अधी०न्याया० के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी०न्याया० का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी०न्याया० ने अपीलांटस को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना गलत एवं अविधिक रूप से अपीलांटस की पीठ पीछे निर्णय व डिक्री पारित की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर बुधवाड़ा में अपीलांटस ने जवाब आदि देने व वकील नियुक्त करने का निवेदन किया था जिस पर अपीलांटस के हस्ताक्षर करवाये गये थे किन्तु अपीलांटस ने निर्णय करने बाबत कोई सहमति नहीं दी थी । शिविर में वादी भी उपस्थित नहीं था तथा ना ही कोई समझाईश हुई थी इसके बावजूद अधी०न्याया० ने सहमति लिखकर लोक अदालत की भावना व न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत जाकर अपीलांटस की पीठ पीछे निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है । वादग्रस्त भूमि अपीलांटस की पुश्तैनी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है जिस पर अपीलांटस व अपीलांटस के पारिवारिक पूर्व खातेदारान के मध्य आपसी बंटवारा होकर अपीलांटस आज दिवस तक काबिज काश्त है । वादग्रस्त भूमि के साबिक खसरा नंबर 641 रकबा 4-6-10 बीघा के 1/2 हिस्से का अपीलांटस के परिवार के संयुक्त खातेदार राजेन्द्र व सुरेन्द्र पुत्रगण रामलाल को बेचान किया एवं उनके द्वारा हाल खसरा नंबर का 1/2 हिस्सा रेस्पो० को बेचान किया तथा अपीलांटस पूर्वजों के बंटवारे अनुसार हाल खसरा नंबर 1661 व 1662 पर काबिज है एवं रेस्पो० संख्या नंबर 1666 व 1667 पर काबिज है । रेस्पो० की नियत में खोट है उसने अपीलांटस को परेशान करने व भूमि हड़पने की नियत से अपीलांटस के कब्जे की भूमि पर अपना कब्जा बताकर झूठे कथनों पर वाद प्रस्तुत किया तथा अपीलांटस की पीठ पीछे डिक्री करवाया है । वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1661 व 1662 पर सिंचाई हेतु अपीलांटस ने 2 किलोमीटर दूर कुएं से पाईप लाईन डाल रखी है एवं उक्त खेतों में भी पाईप लाईन बिछा रखी है जिससे खेत की सिंचाई होती है जिसकी जानकारी रेस्पो० को है एवं खसरा गिरदावरी से भी साबितज है । अपीलांटस सभी अनपढ़ व कम पढ़े लिखे हैं जिनको मात्र हस्ताक्षर करना आता है । अपीलांटस ने सद्भाविक रूप से हस्ताक्षर किये थे परन्तु बाद में रेस्पो० संख्या 1 ने मिलीभगत कर निर्णय व डिक्री प्राप्त की है जो विधि एवं न्यायिक व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होकर निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी०न्याया० का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा प्रकरण अपीलांटस को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु अधी०न्याया० को रिमाण्ड किया जावे ।
5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 गियाद अधि० पेश कर कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा न्याय आपके द्वार शिविल आयोजित होने पर प्रार्थी संख्या 1 से 3 लोक अदालत कैम्प बुधवाड़ा में वाद की जानकारी होने पर उपस्थित हुए एवं वकील नियुक्त कर जवाब आदि देने का निवेदन किया जिस पर शिविर में प्रार्थीगण के आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गये एवं कैम्प पश्चात् तारीख पेशी की जानकारी करने को कहा गया । तत्पश्चात् प्रार्थीगण की बिना सहमति के



राज्य सरकार द्वारा न्याय आपके द्वार  
अधीनस्थ न्यायालय

प्रार्थीगण की पीठ पीछे अधी०न्याया० ने बिना जवाब साक्ष्य सबूत के पत्रावली में दिनांक 22.5.2017 को प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश पारित कर दिये । इसके पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काशत के खसरा नंबर 1661 व 1662 में दखल करने, बेदखल करने का प्रयास किया तब प्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित होकर वकील नियुक्त किया तब वकील ने प्रार्थीगण को जानकारी दी गई कि अप्रार्थी आपके कब्जे के खसरा नंबर 1661 व 1662 को लेना चाहता है । प्राथमिक डिक्री में जवाब नहीं होने का नाजायज फायदा उठाना चाहता है जिससे आप प्राथमिक डिक्री को सक्षम न्यायालय में चुनौती दें । जिस पर प्रार्थीगण ने वकील श्री खींवराज शर्मा से नकल हेतु दिनांक 8.8.2018 को आवेदन करवाया जिस पर दिनांक 10.8.2018 को नकल प्राप्त होने पर अधिवक्ता ने प्रार्थीगण को सूचित किया एवं दिनांक 20.8.2018 को नकल प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो० संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत है । अपीलांटस अधी०न्याया० के समक्ष उपस्थित थे किन्तु इनके द्वारा जानबूझकर जवाब एवं साक्ष्य पेश नहीं किया गया इसलिये अपीलांटस के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है । अपीलांटस ने इस एकतरफा कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु भी कोई चाराजोही नहीं की है । बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजियात संयुक्त खातेदारी एवं संयुक्त कब्जे काशत की आराजियात है जिसमें प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा काशत माना जाता है । अधी०न्याया० की आदेशिका पर अपीलांट के हस्ताक्षर है जिसके आधार पर अधी०न्याया० ने वाद डिक्री कर बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसमें कोई अनियमितता नहीं है । अपीलांटस ने पूर्व में पारिवारिक बंटवारा होने का कथन किया है किन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है । अधी०न्याया० ने संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काशत की आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के विभाजन की डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।
7. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि० का निस्तारण करना उचित समझते हैं । विद्वान वकील अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि० में विलंब के जो कारण अंकित किये हैं वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते हैं । हम न्यायहित में अपीलांटस को प्रकरण में गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते हैं । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।
8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी०न्याया० के समक्ष वादी/रेस्पो० संख्या 1 द्वारा वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 राज०काशत०अधि० के तहत दिनांक 28.5.2016 को पेश किया गया जिस पर अधी०न्याया० ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण/अपीलांटस को जरिये सम्मन तलब किये जाने के आदेश पारित कर वाद में आगामी तारीख पेशी नियत की । दिनांक 29.6.2016 की आदेशिका के अनुसार प्रतिवादीगण/अपीलांटस संख्या 1 से 5 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है । तत्पश्चात् वाद में निर्णय पारित करने से पूर्व लगभग 5 पेशियां नियत की गई किन्तु प्रतिवादीगण/अपीलांटस



*Handwritten signature*  
 जलंधर जिला न्यायालय  
 जलंधर

द्वारा उनके विरुद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु अधी०न्याया० के समक्ष कोई चाराजोही नहीं की गई है । यही नहीं निर्णय दिनांक 22.5.2017 को पत्रावली कैम्प कोर्ट बुधवाड़ा में रखी गई थी । उक्त दिनांक को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने स्वयं अधी०न्याया० के समक्ष उपस्थिति प्रदान की है जिसकी ताईद अधी०न्याया० की आदेशिका पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी होती है । अधी०न्याया० की उक्त कार्यवाही से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण/अपीलांट अधी०न्याया० के समक्ष उपस्थित रहे किन्तु उनके द्वारा एकतरफा कार्यवाही को निरस्त किये जाने तथा जवाब दावा पेश किये जाने बाबत कोई चाराजोही नहीं की गई है । इसलिये अपीलांटस का यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता है कि अधी०न्याया० द्वारा अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा कैम्प में वाद को एकतरफा में निर्णित किया गया है । अधी०न्याया० के निर्णय व प्राथमिक डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पक्षकारान की सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात है । अपीलांटस ने पूर्वजों के समय से पारिवारिक बंटवारा होने का कथन किया है किन्तु अपीलांटस द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष भी उक्त पारिवारिक बंटवारा पेश नहीं किया गया है । अधी०न्याया० ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त निर्णय व प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव प्रतिवादीगण/अपीलांटस की उपस्थिति में तैयार कर भिजवाये गये हैं । यदि अपीलांटस को बंटवारा प्रस्ताव से कोई आपत्ति है तो वे अधी०न्याया० के समक्ष अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व अपना ऐतराज पेश कर सकते हैं । विद्वान अधी०न्याया० ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी०न्याया० द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

9. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.5.2017 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मैघना चौधरी)

राजसूअपील प्राधिकारी,  
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 21.12.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मैघना चौधरी)

राजसूअपील प्राधिकारी,  
अजमेर

